or proposed to be made during the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) and (b) The estimated requirement and net availability of edible oils from all domestic sources during the Oil Year (Nov.—Oct.) 1994-95 was 69.80 lakh MT and 64.00 lakh MT respectively.

(c) The import of edible oils (except coconut oil, palm kernel oil, RBD palm oil and RBD palm stearin) is allowed under Open General Licence. Central Government imports RBD palmolein for supply through the Public Distribution System (PDS). During the current financial year 1995-96 (upto October) the STC has imported 1.49 lakh tonnes of RBD palmolein for PDS.

बाल श्रमिकों हेतु विद्यालय

1410. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनन्य रूप से बाल श्रमिकों हेतु विद्यालय खोलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे बाल श्रमिकों के माता-पिता की आय में आई कमी की क्षतिपूर्ति करने का भी विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (रा०बा०श्र०प०) स्कीम के अधीन, बालकों को कार्य से निकाला जाता है और उन्हें विशेष स्कूलों में भर्ती कर दिया जाता है जहां उन्हें प्राइमरी स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे छठी कक्षा से आगे के स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। इन बालकों को वृत्तिकाएं, पोषणाहार और स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान की जाती है। विशेष स्कूलों की स्थापना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अधीन एक प्रमुख क्रियाकलाप है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत कार्य से निकाले गए और विशेष स्कूलों में भर्ती कराए गए बालकों को 100 रुपए की वृत्तिका प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कार्य जगत से निकाले गए बालकों के माता-पिता के आय-स्तरों को सरकार की अन्य स्कीमों के माध्यम से ऊपर उठाने की परिकल्पना की गई है। इन स्कीमों में अन्यों के साथ-साथ आई आर डी पी, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं को उचित रूप से अभिकेन्द्रित करने के लिए, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

Suppy of Essential Commodities to Maharashtra

1411. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the supply of essential commodities made to the State of Maharashtra monthwise for the last one year vis-a-vis the demand made/requirement, commodity-wise and the basis for release of the quota;

(b) whether the Government of Maharashtra made some proposal to the Central Government for allotment of kerosene;

(c) if so, details of action taken/proposed thereon; and

(d) the details of major policy changes sought by the State Government and action taken/proposed thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (c) The details showing the allocation and offtake of commodities for the Public Distribution System (PDS) in